

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 24 फरवरी, 2015 / 5 फाल्गुन, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 फरवरी, 2015

संख्याः ई०एक्स०एन०-एफ(10)-1/94-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 20 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 34 की उपधारा(1), हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 14—ख और हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5(1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्याः

ई०एक्स०एन—एफ(10)—2 / 83 तारीख 28.09.1991 द्वारा जिला सिरमौर के राजबन में स्थापित बहुउद्देशीय बैरियर को तुरन्त प्रभाव से बन्द करने का आदेश देते हैं ।

> आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-1/94-II dated 21.02.2015. as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 21st February, 2015

No.EXN-F(10)-1/94-II.—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 34 of Himachal Pradesh Value Added Tax Act,2005 (Act No. 12 of 2005), section 14-B of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (Act No.15 of 1955) and section 5(1) of the Himachal Pradesh Taxation(on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999) read with section 20 of the Himachal Pradesh General Clause Act, 1968 (Act No.16 of 1969) the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order the closure of Multipurpose barrier at Rajban in Sirmour District established vide notification No. EXNF(10)-2/83, dated 28.09.1991 with immediate effect.

By order, Sd/-Principal Secretary (E&T).

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 21 फरवरी, 2015

संख्याः पीसीएच—एचए—(1) 11/2010—ए०ई०.—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद् में सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2013 के प्रारूप को इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 9 जुलाई, 2013 द्वारा, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 के उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित, जनसाधारण से आपेक्ष और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए, तारीख 22 जुलाई, 2013 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के दौरान प्राप्त हुए आक्षेपों / सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया है ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

- 1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषदों में सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2015 है।
 - 2. परिभाषाएं.--(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) ''अधिनियम'' से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 अभिप्रेत है; और
 - (ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं।
- (2) उन शब्दों और पदों को जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं।
- 3. पदनाम तथा पदों की संख्या.—सहायक अभियन्ता के पदों की, जिला परिषदों में, ऐसी संख्या होगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गई हो।
- 4. वेतनमान.—सहायक अभियन्ता के पद के लिए वेतनमान, पे बेण्ड—II—15660—39100 / रूपए +5400 / रूपए ग्रेड पे होगा।
 - 5. पद का प्रकार (चयन अथवा अचयन पद).— चयन पद।
- 6. परिविक्षा की अवधि.—सहायक अभियन्ता दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, जिसका एक वर्ष से अनिधक ऐसी और अविध के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा निदेशक विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
 - 7. नियुक्ति की पद्धति.—शतप्रतिशत प्रोन्नित द्वारा ऐसा न होने पर सैकेण्डमैंट आधार पर।
- 8. प्रोन्नित की पद्धित.—सहायक अभियन्ता को राज्य स्तर पर तैयार की गई पारस्परिक विष्ठता के आधार पर, जिला परिषदों के नियमित स्नातक किनष्ठ अभियन्ताओं में से प्रोन्नित द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिनका कम से कम तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यिद कोई है, को सिम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो और गैर स्नातक किनष्ठ अभियन्ताओं की दशा में सात वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यिद कोई है, को सिम्मिलित करके सात वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।
- 9. नियुक्ति प्राधिकारी.—सम्बद्ध जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी होगा।
 - 10. विभागीय प्रोन्नित समिति.—-जैसी निदेशक द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
- 11. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय—समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / पिछड़े वर्गों / अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए, सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगी।
 - 12. जॉब चार्ट.—जैसा निदेशक, पंचायती राज द्वारा समय—समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।
- 13. प्रशिक्षण और परीक्षा.—सेवा के सदस्यों को ऐसी परीक्षा अर्हित करनी होगी और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, जैसा निदेशक, पंचायती राज द्वारा समय—समय पर विहित किया जाए।

- 14. शिथिल करने की शिक्त.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
- 15. निरसन और व्यावृतियाँ.—(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख को और से, अधिसूचना संख्या पी०सी०एच०–एच०बी०(1)36 / 01–ऐई, तारीख 20 अगस्त,2001 द्वारा, जिला परिषद द्वारा संविदा आधार पर सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति हेतु अधिसूचित स्कीम, निरसित हो जाएगी।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित स्कीम के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, (मनीषा नंदा), प्रधान सचिव (पंचायती राज)।

[Authoritative English text of this Department Notification Number PCH-HA(1) 11 / 2010-A.E. dated 23-2-2015 as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India)].

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 23rd February, 2015

No. PCH-HA (1) 11 /2010-A.E.—Whereas the draft Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of Service of Assistant Engineers in Zila Parishads) Rules, 2013 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 22nd July, 2013 for inviting objections and suggestions from the general public, vide this department notification of even number dated 9th July, 2013 as required under section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994);

And whereas, the objection(s)/suggestion(s) received during the stipulated period have been duly considered by the State Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:—

- 1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of Service of Assistant Engineers in Zila Parishads) Rules, 2015.
 - **2. Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "Act" means the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994; and
 - (b) "Form" means form appended to these rules.
- (2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Act.

- **3. Nomenclature and number of Posts.**—There shall be such number of posts of Assistant Engineers as sanctioned by the State Government in the Zila Parishads.
- **4. Scale of Pay.**—The Scale of Pay for the post of Assistant Engineer shall be Pay Band-II -Rs.15660-39100 + 5400 Grade Pay.
 - 5. Type of post (whether selection or non selection post.).—Selection Post.
- **6. Period of Probation.**—The Assistant Engineer shall remain under probation for a period of two years subject to such further extension for a period of not exceeding one year, as may be ordered by the Director in special circumstances and reasons whereof shall be recorded in writing.
 - 7. **Mode of appointment.**—100% by promotion, failing which on secondment basis.
- **8. Method of promotion.**—The Assistant Engineers shall be appointed by promotion from amongst regular graduate Junior Engineers of Zila Parishads having at least 3 years regular service or regular combined with continuous ad-hoc service rendered, if any, in the grade and in case of non-graduate Junior Engineers 7 years regular service or regular combined with continuous ad-hoc service rendered, if any, in the grade, on the basis of inter-se-seniority maintained at the State level.
- **9. Appointing Authority.**—(1) The Chief Executive Officer of Zila Prishad concerned shall be the appointing authority.
- **10. Departmental Promotion Committee.**—As may be constituted by the Director from time to time.
- 11. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Backward Classes/ Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
 - 12. Job Chart.—As may be specified by the Director Panchayati Raj from time to time.
- 13. Training & Examination.—The members of the service shall have to qualify such examination and shall undergo such training as may be specified by the Director Panchayati Raj from time to time.
- 14. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order relax any of the provisions(s) of these rules with respect to any class or category of person (s) or post (s).
- **15. Repeal & Savings.**—(1) On and from the date of commencement of these rules, the Scheme notified for the appointment of Assistant Engineers on contract basis by Zila Parishad vide notification No. PCH-HB (1) 36/01-AE, dated 20th August, 2001 shall stand repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken, under the scheme so repealed, shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23th February, 2015

No. FFE-B-E(3)14/2012-I.—In pursuance of the orders dated 21-11-2013 passed by Hon'ble National Green Tribunal in application No. 249(THC) of 2013- Pawan Kumar Vs State of HP, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to frame the Tibetan Rehabilitation Policy, Himachal Pradesh annexed to this notification with immediate effect.

By order,
Sd/-
Addl. Chief Secretary (Forests).

TIBETAN REHABILITATION POLICY, HIMACHAL PRADESH

When China occupied Tibet, many Tibetans under the leadership of His Holiness The Dalai Lama, came to India along with their families and have been living in India since the past 50 years. His Holiness Dalai Lama heading the Central Tibetan Relief Committee is stationed at Mcleodganj Dharamshala. There are many Tibetan Refugee families living in Dharamshala, Riwalsar (Mandi) and other parts of the State and families were allowed to occupy the Govt. land. During 2012, Shri. Pawan Kumar S/o Sh. Partap Singh, R/o Village Dhangu, P.O. Ratti, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. filed CWP No. 2228/2012 in the Hon'ble High Court alleging large scale encroachment of forest land by Tibetans in Mandi, Kullu and Kangra Districts. The Forest Department took cognigence and started eviction proceedings against 210 Tibetan Refugee families at Mcleodganj Dharamshala and 5 families at Riwalsar (Mandi). The matter was subsequently considered by Hon'ble National Green Tribunal as application No. 249(THC) 2013 who vide its order dated 21.11.2013 directed State Government to frame a common policy for removal of encroachment including disposal of muck in consultation with Archaeological Survey of India.

- 2. During February, 2014, the Ministry of Home Affairs, Govt. of India advised State Government to keep the eviction process held in abeyance and wait for further advisory on the issue as the settlement of Tibetan Refugees is a commitment of Govt. of India and eviction may have international ramification. Hon'ble Green Tribunal vide its order dated 09.01.2015 ordered to formulate policy in the matter.
- 3. The land in question is forest land but the unauthorised occupation by Tibetan Refugees is prior to the enactment of Forest Conservation Act. At that time, the State Govt. was empowered to allow occupation on Govt, land to these refugees as the rehabilitation of Tibetan Refugees is commitment of Govt. of India and the issue has international ramification. Hence, now the State Govt. does not want to conclude the eviction proceedings initiated by DFO cum Collector Dharamshala. The culmination of eviction orders may create law and order problem as multistorey structures are involved and the disposal of muck will be a big problem instead, the State is framing Tibetan Rehabilitation Policy to settle the issue which is based on The Tibetan Rehabilitation Policy, 2014 of Govt. of India.

- 4. The Tibetan Refugees are settled in different part of the State occupying Govt. land and have constructed houses. The following guidelines are laid down for the rehabilitation of Tibetan Refugees in the State:
 - i. The land under occupation by the Tibetan Refugees should not be disturbed. However, in case of any court order by which they need to be dispossessed than they should be relocated by giving afresh piece of land of equal of larger size.
 - ii. The revenue and forest department will jointly identify the Tibetan Refugees being bonafide settlers and those who are deliberate encroachers. The bonafide settlers will be settled under this policy and the deliberate encroachers evicted under existing law.
 - iii. In case of occupation on non forest land, long term lease agreement should be signed with individual Tibetan but with the duly authorised representative of the Central Tibetan Relief Committee. The local Magistrate may sign the lease deed on behalf of State Govt., Copy of the Standard Lease Document is annexed as **Annexure-A**. The lease agreement should be renewed periodically. The Tibetan Refugee families should be authorized to retain possession of land and houses on a temporary basis.
 - iv. The Central Tibetan Relief Committee (CTRC) should be allowed to decide which portion of the land can be used for residential, agricultural, commercial, religious activity or any such activity so that the Tibetan families can follow their culture and religion unhindered and yet are able to make an economic living out of the land.
 - v. The lease should be signed for a period of 20 years or till it is revoked/cancelled (by an order of the Government of HP or till the rehabilitation facilities provided to Tibetan Refugees are cancelled or withdrawn by the Government of HP on the advice of Government of India) whichever is earlier.
 - vi. A rent Tenancy Certificate must be issued and the State Government shall collect the dues, Revenue, Fees from the Local Settlement Officer/Welfare Officer of the Tibetan Settlement. The Rent Tenancy Certificate should clearly mention the following:—
 - Owner Government
 - Lessee CTRC
 - Cultivated by (name of the Tibetan Refugee who is cultivating the land)
 - vii. Proper demarcation, preferably with boundary fencing etc., of land allotted for Tibetan Refugee use, should be ensured by the District Administration to avoid confrontation/dispute between locals and Tibetan Refugees.
 - viii. The Settlement/Welfare Officers of the Tibetan Settlements shall maintain a register and update the same annually, giving the details of individuals/family members of the settlements to the Local District Magistrate. The local District Magistrate shall be competent to inspect the register to ensure that it is annually updated.
 - ix. The State Government may consider allotting extra land depending upon the need and the population increase of the Tibetan Refugees.

- x. In case of Forest Land, prior approval from Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India will be taken under Forest Conservation Act, 1980 as per provisions under Annexure IV of the guidelines with the intervention of Ministry of Home Affairs and Ministry of External Affairs. After the approval, the long term lease agreement may be signed as per procedure mentioned above for non forest land.
- xi. The Tibetan Refugees shall continue to get the benefits of various development schemes of Govt. of India and Govt. of HP as allowed from time to time.

ANNEXURE-A

STANDARD LEASE DOCUMENT

This lease, made on thisday of.......Two Thousand and, between the Governor of Himachal Pradesh (hereafter called the lessor) of the one part and His Holiness The Dalai Lama's Central Tibetan Relief Committee (CTRC) at, the other part (hereinafter called "The Lessee" which expression shall, unless the context requires another different meaning, includes his heirs, executors, representatives and permitted assigns)."

Whereas the Lessor has agreed to transfer to the Lessee the land described in the schedule below on lease for 20 years, or till it is revoked/cancelled by an order of the Central Government/Lessor, upon the terms and conditions hereinafter appearing and contained.

Now this deed witnesseth that in consideration of the rent herein after reserved and of the covenants by the Lessee hereinafter contained, the LESSOR doth demise unto the LESSEE all that piece of land described in the schedule hereunder for a term of 20 years subject to the following terms and conditions viz..

- 1. The lease is liable to cancellation if it is found that it was grossly inequitable or was made under a mistake of fact or owing to misrepresentation or fraud or that there was an irregularity in the procedure. In the event of such cancellation of the lease the lessee shall not be entitled to any compensation for any loss or damage.
- 2. The Lessee shall pay a sum of Rs. 100/- as security deposit for the due fulfilment and observance by him of the conditions contained in the lease. The sum of deposited shall be liable to be forfeited by the Lessor in the event of failure by the lessee to fulfil any of the conditions of lease.
- 4. If the Lessee fails to pay the Lessor any sums payable under the lease on the respective dates on which they are made payable, he shall pay interest at 12% per annum on such amounts from the dates on which they were so payable until the date of payment or recovery.

- 5. The Lessee shall use the land for the purpose of agriculture/ residential/ commercial/religious activity, in keeping with the Tibetan culture, religious and livelihood.
- 6. The legally authorized resident shall not do any act which is destructive or permanently injurious to the land.
- 7. The land shall be in possession of the Lessee who in turn may decide the usage as per the Tibetan Rehabilitation Policy notified by the Government of India/Govt. of HP..
- 8. The Lessee shall not sub-let mortgage or otherwise transfer his leasehold right. The Lessee may offer such leased lands as security for raising loans from cooperative society/Scheduled Bank for undertaking any agricultural/economic/commercial or social/educational activity.
- 9. The lease shall be terminated when the rehabilitation facilities provided to the Tibetan Refugees are cancelled or withdrawn by the Government of India.
- 10. The land shall not be used for political meetings.
- 11. The Lessee shall permit the Officers of the Lessor with or without workmen at all times to enter upon the lands aforesaid to view the conditions and state thereof.
- 12. The Lessee shall not assign or sublet the benefits arising under this lease or any part thereof without the previous written permission of the Lessor.
- 13. (a) The Lessor reserves to themselves the right of all trees their branches and roots which exist at the time of lease (which are described in the schedule attached) as well as those which may grow subsequently on the lands leased and the Lessor shall be at liberty to cut or dig out any such trees or their roots and branches and remove them from the land in question and dispose them of at their leisure without any compensation/Bonus to the lessee. The Lessee shall not be entitled to cut and remove them without the previous written permission of the Lessor.
- (b) The Lessee shall take all reasonable measures to the satisfaction of the Deputy Commissioner/Administrator/Districts Collector/Forest Authorities for the protection of the trees pre-existing from theft or damage and for the careful protection of the immature trees growing on the lands.
- (c) The Lessee shall take steps to see that marks made by the officers of the Lessor on the trees are preserved and are not tampered with.
- (d) In the event of the infringement, or failure to observe any of the conditions mentioned in (a), (b) or (c) above, the Lessee shall pay the Lessor such compensation as determined by the Deputy Commissioner/Administrator/Districts Collector/Forest Authorities. The State Government shall also be at liberty to cancel the lease and enter on the land and the entire land shall thereupon vest absolutely in the State Government in that case the Lessee shall not be entitled to any compensation whatsoever.
- 14. The Lessee/legally authorized resident shall not erect any new buildings or structures of a permanent character on the lessor land without the previous written sanction of the

Lessor. Up-gradation/improvement of existing structures may be done by the Lessee under information to the Lessor.

- 15. The Lessee shall not cut any live trees without the previous permission of the Deputy Commissioner/Administrator/District Collector/Forest Authorities. The withered and wind fallen trees shall also be the property of the Lessor and shall be handed over to the nearby forest authority or other authorities appointed by the Lessor to look after the lands leased to the Tibetan Refugees.
- 16. The sale proceeds of withered and wind fallen trees and those cut under condition (15) shall be credited to the Lessor.
- 17. The Lessee shall have no rights whatsoever to, any trees standing on the land or to their usufruct.
- 18. The Usufruct of the trees may be leased out in auction by the officers of the Lessor according to the practice in vogue in the district and the Lessee shall allow a right of passage to persons to whom the usufruct of the trees is so granted by the Lessor.
- 19. The Lessee shall not, without the previous written sanction of the Deputy Commissioner/Administrator/any authorities nominated by the Lessor, permit any person to use the land or any structure thereon or any portion of the land or structure except as provided in conditions (5).
- 20. The Lessee shall on the termination or revocation of this lease, restore the said land to the Lessor in as good a condition as is consistent with the foregoing conditions.
- 21. The Lessee shall be answerable to the Lessor for all or any injury or damage done to the said land and other Government property thereon except as is permitted by the foregoing conditions.
- 22. The Lessor may revoke the lease wholly or partly, if the sums specified in condition (3) above or any part thereof shall remain unpaid for 15 days after they have become payable whether formally demanded or not, OR if the Lessee shall have contravened any of the conditions of the lease herein contained; and assume control or otherwise dispose of all or any part of the land, any buildings, fences and structures thereon and the Lessee shall not be entitled to any compensation therefor.
- 23. If the amount specified in condition (3) or (4) above or any part thereof is in arrears, it shall also be competent for the Lessor to recover the same from the Lessee as an arrear of land revenue.
- 24. The Lessor may terminate the lease without prejudice to any right of action or remedy of the Government in respect of any breach of any of the foregoing conditions. The Lessee shall not, in the case of such revocation or termination, be entitled to any compensation in respect of any structures on the land or any improvements effected by him to the land or for the loss caused by the interruption of his occupation.
- 25. In the event of termination of the lease under condition 22 or 24, the Lessor shall be at liberty to levy proportionate rental upto the date of such termination.

- 26. The Lessee shall protect and maintain, at all times, the contour bunds and other structures constructed at the cost of Lessor at the time of leasing the land.
- 27. The lease includes all rights, easements, appurtenances belonging to the land or reported to belong to it or usually held or enjoyed with it. The existing and customary rights of Lessor and the public, in roads and paths and rivers streams and channels running through or bounding the land and the right of Government to the mines and quarries adjacent to the land are however reserved and are in no way affected by the lease.
- 28. If the land or any portion of land is required for any public purpose or for any administrative purpose, the Lessor shall, at the expiry of a notice of fifteen days to that effect that the said land is required for such purpose, be at a liberty to take possession of the land with structures.
- 29. The Lessee, on the determination of the lease, shall handover the demised premises with all structures erected thereon.
- 30. Notwithstanding anything contained above, the Central Government/Lessor may, at any time, cancel the lease, without assigning any reason thereof. However, a prior notice of 3 months shall be given before revoking the lease.
- 31. The lease is subject to the provisions of Land Acts of Himachal Pradesh and Rules made there under as amended from time to time.

SCHEDULE

District	Sub Division	Tehsil	Revenue Village	Khasra No.	Forest Boundaries
					N.S.E.W.
1	2	3	4	5	6 7

Signed by Lessee

Signed by the Lessor

In the Presence of

Date:

Station

1.

2.

In the court of Shri Balwan Chand (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sujanpur, District Hamirpur, H.P.-176110

In the matter of .

- 1. Rakesh Kumar, aged 31 years s/o Shri Jai Ram, r/o Village Bir Bigehra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).
- 2. Neelam Singh, aged 18 years d/o Shri Ajit Singh, r/o Ward No. 1, Palampur, District Kangra (H.P.) ... Applicants.

Versus

General public

Subject.— Notice of the Intended Marriage.

Rakesh Kumar and Neelam Singh have filed an application in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 12-3-2015. The objections received after 12-3-2015 will not entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 2-2-2015 under my hand and seal of the court.

Seal. BALWANT CHAND,

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Shri Balwan Chand (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sujanpur, District Hamirpur (H. P.)

In the matter of:

- 1. Anil Kumar Katoch, aged 29 years s/o Shri Partap Chand, r/o Village Buhar, P.O. Tihra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).
- 2. Aditya Panchaksharan, aged 26 years d/o Shri K. Panchaksharan, r/o Village Dwarka Street-2, Sidhart Kunj, New Delhi-1 . . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001).

Anil Kumar Katoch and Aditya Panchaksharan have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 5-12-2014 in Murali Manohar Mandir at Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 3-3-2015. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 2-2-2015 under my hand and seal of the court.

Seal.

BALWAN CHAND,

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी (Marriage Officer) बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

- 1. सपना कुमारी पुत्री सकीन चन्द, वासी महाल व डाकघर समताना, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
- 2. बालक राम पुत्र जोगिन्दर सिंह, वासी महाल ठाठल जंगल, डाकघर गंगलोह, तहसील झन्डुता, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

ं प्रतिवादी।

सपना कुमारी पुत्री सकीन चन्द, वासी महाल व डाकघर समताना, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में बालक राम पुत्र जोगिन्दर सिंह, वासी महाल ठाठल जंगल, डाकघर गंगलोह, तहसील झन्डुता, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) से विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता—पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 12—3—2015 को प्रातः 10 बजे इस न्यायालय में उजर कर सकते हैं इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 12-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताारित / – विवाह पंजीकरण अधिकारी, बडसर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)। ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

- 1. अनिल कुमार सपुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव व डाकघर धबीरी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
- 2. संजूली बगलारी सपुत्री श्री सिनंद बगलारी, निवासी टाउन नं0 2, बारी गांव (पार्ट) पी0 एस0 उदलगुड़ी, उप—मण्डल उदलगुड़ी, जिला उदलगुड़ी, असम (भारत)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

संजूली बगलारी सपुत्री श्री सिनंद बगलारी, निवासी टाउन नं0 2, बारी गांव (पार्ट) पी0 एस0 उदलगुड़ी, उप—मण्डल उदलगुड़ी, जिला उदलगुड़ी, असम (भारत) ने इस न्यायालय में अनिल कुमार सपुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव व डाकघर धबीरी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) से विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता—पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 18—3—2015 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में उजर कर सकते हैं इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 13-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताारित / – विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

Proclamation of Sale under Section 85 of the H.P. Land Revenue Act

Whereas, arrear of land revenue amounting to Rs. 1,05,000/- has accured in respect of the land described in the schedule below in the estate and the sanction of the Divisional Commissioner, Mandi Division has conveyed *vide* letter No. Commr. Mandi (LR) (3) (4)/87-5703, dated 24-11-2014 under section 81 of the H.P. Land Revenue Act to the sale of the immovable property, detailed in the annexed schedule for the recovery of the said arrear, this is to give notice that the said immovable property will be sold by auction at Patwar Khana Banal on the 20th day of March at 11.30 A.M. Land revenue amounting to Rs. (to be assessed later) per annum on the above said estate payable in respect of the said holding. Any person intenting to claim a right of pre-emption must on pain for forfeiting the right give notice of this intention to me on an office day before that fixed above for the sale. This sale will be made subject to the provisions of section 76, section 85(d) of the H.P. Land Revenue Act free from all encumbrances.

SCHEDULE OF PROPERTY:

OWNER: NARESH AZAD s/o RATTAN CHAND

1/12 share *i.e.* 0K-12M comprised in khata No. 41, khatauni No. 48, kita 11, total area measuring 07K-02M situated in Tika Barain, Mouza Karot, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur as per jamabandi for the year 2010-2011.

Place : Hamirpur

Sd/-

District Collector, Hamirpur (H.P.).

Dated: 6-2-2015

Proclamation of Sale under Section 85 of the H.P. Land Revenue Act

Whereas, arrear of land revenue amounting to Rs. 29,400/- has accured in respect of the land described in the schedule below in the estate and the sanction of the Divisional Commissioner, Mandi Division has conveyed *vide* letter No. Commr. Mandi (LR) (3) (4)/87-5704, dated 24-11-2014 under section 81 of the H.P. Land Revenue Act to the sale of the immovable property, detailed in the annexed schedule for the recovery of the said arrear, this is to give notice that the said immovable property will be sold by auction at Patwar Khana Dhaned on the 26th day of March at 11.30 A.M. Land revenue amounting to Rs. (to be assessed later) per annum on the above said estate payable in respect of the said holding. Any person intending to claim a right of pre-emption must on pain for forfeiting the right give notice of this intention to me on an office day before that fixed above for the sale. This sale will be made subject to the provisions of section 76, section 85(d) of the H.P. Land Revenue Act free from all encumbrances.

SCHEDULE OF PROPERTY:

OWNER: AJUDHIYA DASS s/o RUNKA RAM

Khata No. 10, khatauni No. 20, Kita Khasra No's. 698 and 1100 total area measuring 00-03-99 hect. situated in Tika Kirwin, Mouza Dhaned, Tehsil Hamirpur, District Hamirpur as per jamabandi for the year 2007-2008.

Place : Hamirpur Dated : 6-2-2015

Sd/-

District Collector, Hamirpur (H.P.).

In the Court of Shri Rakesh Kumar Sharma (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H. P.)

In the matter of:

- 1. Karnail Singh, aged 31 years s/o Shri Shinda Singh, r/o House No. 5G, Ward No. 10, Hargovind Nagar, New Abadi, Ram Colony Hoshiarpur, Punjab-146 001.
- 2. Nischala Devi, aged 30 years d/o Shri Rattan Chand, r/o Village Bassi, P.O. &, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) . . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001).

Karnail Singh and Nischala Devi have filed an application alongwith affidavits in this court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 4-1-2015 at Bassi, P.O. & Tehsil Bhoranj, District Hamirpur as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 17-3-2015. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 16-2-2015 under my hand and seal of the court.

Seal.

RAKESH KUMAR SHARMA, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Shri Viney Dhiman (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H. P.)

In the matter of:

- 1. Mr. Gopi Lal s/o Mr. Kabir, r/o H.No. 161, C.B. Yol-W No.Part-I, Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.)
- 2. Mrs. Sangita, d/o Ganga Singh, r/o Village Shaminala, Post Office Jagatsukh, Tehsil Manali, District Kullu H.P. presently wife of Mr. Gopi Pal, r/o H.No. 161, C.B. Yol-W No.Part-I, Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) . . *Applicants*.

Versus

General Public

Subject.—An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Mr. Gopi Lal and Mrs. Sangita have presented an application on dated 12-2-2015 in this court for registration of the marriage under Special Marriage Act, 1954 hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 11-3-2015 at 11.00 A.M. to object registration of above marriage personally or through any authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 12th day of February, 2015.

Seal.

In the Court of Shri Viney Dhiman (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H. P.)

In the matter of:

- 1. Yeshi, aged 72 years, d/o Thinley, Village & P.O. Losar, Tehsil Kaza, District Lahaul & Spiti at present w/o Mr. Gurmad, r/o House No. 19, Dickeyling, Tibetan Colony, P.O. & Tehsil Manali, District Kullu (H.P.)
- 2. Gurmad, aged 81 years, s/o Tobga, r/o House No. 19, Dickeyling, Tibetan Colony, P.O. & Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) . . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Yeshi and Gurmad have presented an application on dated 12-2-2015 in this court for registration of the marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any persons have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 11-3-2015 to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 12th day of February, 2015.

Seal. VINEY DHIMAN,

Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.).

In the Court of Shri Viney Dhiman (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H. P.)

In the matter of:

Panna Lal s/o Shri Chande Ram, r/o Village Rankhru, P.O. Patlikuhal, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) & Sunita d/o Shri Dhan Bahadur, r/o Village Karadsu, P.O. Seobagh, Tehsil and District Kullu (H.P.).

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Panna Lal s/o Shri Chande Ram, r/o Village Rankhru, P.O. Patlikuhal, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) & Sunita d/o Shri Dhan Bahadur, r/o Village Karadsu, P.O. Seobagh, Tehsil and District Kullu (H.P.) have presented an application on 10-2-2015 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby

issued for the information of general public that if any person have any objection for the registration of the marriage can appear in this court on 9-3-2015 at 11.00 A.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 10th day of February, 2015.

Seal.

VINEY DHIMAN,

Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali,, District Kullu (H.P.).

ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 4 / 2015

तारीख दायर : 12-2-2015

श्री ज्वाला दास पुत्र श्री तेजू राम, निवासी गांव व डा० मझेवली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत इन्द्राज अराजी खाता/खतौनी नं0 78/174, कित्ते 8, रकबा तादादी 00-64-27 है0, वाका चक मझेवली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्री ज्वाला दास पुत्र श्री तेजू राम, निवासी गांव व डा० मझेवली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र०) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता/खतौनी नं0 78/174, कित्ते 8, रकबा तादादी 00—64—27 है0, वाका चक मझेवली के खाना मालिक में वादी का नाम गोसरु पुत्र तेजू दर्शाया गया है, जो गलत है। आवेदक का सही नाम ज्वाला दास पुत्र श्री तेजू राम है जिसकी पुष्टि हेतु वादी ने छायाप्रति फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड व शपथ—पत्र संलग्न आवेदन कर रखे हैं जिसमें वादी का नाम ज्वाला दास पुत्र तेजू राम दर्शाया गया है। वादी अपना नाम उपरोक्त माल कागजात में गोसरु पुत्र तेजू के स्थान पर ज्वाला दास पुत्र तेजू राम दरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को वादी का नाम उपरोक्त माल कागजात में गोसरु पुत्र तेजू के स्थान पर ज्वाला दास पुत्र तेजू राम दरुस्त करने बारे कोई आपित हो तो दिनांक 12—3—2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपित दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम माल कागजात में दरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 12-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 2/2015

तारीख दायर : 5-2-2015

कु0 शिखा अग्रवाल पुत्री स्व0 श्री चन्द्र प्रकाश अग्रवाल, निवासी वार्ड नं0 3, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना—पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 1978 की धारा 10/3 के अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे। नोटिस बनाम आम जनता।

कु0 शिखा अग्रवाल पुत्री स्व0 श्री चन्द्र प्रकाश अग्रवाल, निवासी वार्ड नं0 3, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि 17—2—1990 का पंजीकरण नगरपालिका परिषद् रामपुर में समय पर दर्ज न करवा सकी है। प्रार्थी अब अपना नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण स्थानीय नगरपालिका परिषद् के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक के नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण स्थानीय नगरपालिका परिषद् अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपित्त हो तो दिनांक 12—3—2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपित्त दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नगरपालिका अभिलेख में नाम व जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 5-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 3 / 2015

तारीख दायर : 5-2-2015

श्री रेशू राम पुत्र स्व0 श्री रेलू राम, निवासी गांव गसो, डा0 झाकड़ी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

ं प्रतिवादी।

दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत इन्द्राज अराजी खाता / खतौनी नं0 41 / 94, कित्ते 5, रकबा तादादी 00—69—69 है0, वाका चक गसो, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्री रेशू राम पुत्र स्व० श्री रेलू राम, निवासी गांव गसो, डा० झाकड़ी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि०प्र०) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता/खतौनी नं० 41/94, कित्ते 5, रकबा तादादी 00-69-69 है0, वाका चक गसो के कागजात माल में वादी का नाम सुरेश पुत्र रेलू दर्शाया गया है, जो गलत है। आवेदक का सही नाम रेशू राम पुत्र स्व0 श्री रेलू राम है जिसकी पुष्टि हेतु वादी ने छायाप्रति नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड व शपथ-पत्र संलग्न आवेदन कर रखे हैं जिसमें वादी का नाम रेशू राम पुत्र रेलू राम दर्शाया गया है। वादी अपना नाम उपरोक्त माल कागजात में सुरेश पुत्र रेलू के स्थान पर रेशू राम पुत्र रेलू राम दरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को वादी का नाम उपरोक्त माल कागजात में सुरेश पुत्र रेलू के स्थान पर रेशू राम पुत्र रेलू राम दरुस्त करने बारे कोई आपित हो तो दिनांक 12—3—2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपित दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम माल कागजात में दरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 5-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

CORRECTION OF DOB

I, Tashi Lhamo, Registration No. Sep./Edu/109/12/TIB/D/Shala, d/o Shri Kyiloe, Upper TCV School, Dharamshala Cantt., District Kangra, H.P. declare that my DOB in Certificate of Class X CBSE school record wrongly entered as 1-1-1995. My correct DOB is 1-10-1995. Concerned note.

TASHI LHAMO d/o Shri Kyiloe, Upper TCV School, Dharamshala Cantt., District Kangra (H.P.).